फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 217 प्रभात जयपुर, गुरूवार 12 मार्च, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

Her Weapon? Archives

European scholars assumed the Aztecs had crude timekeeping methods. Zelia proved they had multiple interlocking calendar systems of extraordinary mathematical sophistication

Your Alarm Clock Is Egyptian Technology

Travancore and the Question of Sovereignty

विधानसभा चुनाव से पूर्व एक भारी भ्रष्टाचार का भांडा फूटेगा, केरल की कांग्रेस इकाई में?

इस ''स्कैण्डल'' की मुख्य कालिख पार्टी के उस नेता के मुंह पर पुतेगी, जो राहुल गांधी के बहुत प्रिय व नज़दीकी बताए जाते हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मार्च। केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले की चपेट में आती दिखाई दे रही है। यह मामला राहुल गांधी के एक करीबी सहयोगी और बेहद खास माने जाने वाले नेता से जुड़ा बताया जा रहा है।

केरल भ्रष्टाचार के मामले में बेहद संवेदनशील राज्य माना जाता है। यहां एक समय पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण को मात्र एक लाख रुपये के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, जो किसी भी हिसाब से बहुत छोटी रकम है।

हरियाणा में भाजपा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से इन आरोपों पर सफाई देने और अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की।

हरियाणा के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं और उनमें से एक के निजी सहायक द्वारा ठगा गया है। इस व्यक्ति ने पहले केरल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो बाद में सभी टीवी चैनलों पर वायरल हो गई।

आरोप है कि विधानसभा का टिकट दिलाने के वादे पर पैसा लिया गया। यह रकम एक नेता के संसद भवन स्थित बैंक खाते में जमा कराई गई, जबकि कुछ रकम उनके निजी सहायक के खाते में जमा कराई गई।

बाद में उस निजी सहायक को संबंधित नेता ने पद से हटा दिया। बताया जाता है कि यह नेता आज-कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में काफी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- आरोप है कि इस नेता व उसके निजी सचिव ने हरियाणा के एक नेता से पैसे लिये, उनको टिकट दिलाने का वादा करके। उक्त नेता ने पार्लियामेंट हाउस के बैंक के अपने एकाउंट में पैसे लिये। ऐसा ही इस नेता के पी.ए. ने भी किया।
- मामला उजागर होने पर, उक्त नेता ने अपने पी.ए. को उसके पद से हटा दिया।
- जैसा कि विदित ही है, राजनीतिज्ञों का भ्रष्टाचार बहुत संदेवनशील विषय है केरल में। पूर्व मु.मंत्री करुणाकरण को अपने मु.मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, उन पर एक लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था, हालांकि, तब भी और अब भी एक लाख रुपए की रिश्वत आम तौर पर बड़ी बात नहीं मानी जाती थी।
- भाजपा व मार्क्सवादी पार्टी, इस नए स्कैण्डल को भारी मुद्दा बना रहे हैं तथा कांग्रेस को आशंका है कि इस मुद्दे से विधानसभा चुनावों पर काफी असर पड़ सकता है।
- वैसे, लगातार दो विधानसभा चुनावों में हार के बाद, कांग्रेस को बहुत आशा है कि इस बार वह इन चुनाव में जरुर जीत हासिल करेगी।

स्पीकर ओम बिड़ला को हटाने का प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली, 11 मार्च। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ विपक्ष के उन्हें पद से हटाए जाने का प्रस्ताव बुधवार को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह के वक्तव्य के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ। प्रस्ताव कांग्रेस के सदस्य मोहम्मद जावेद ने पेश किया था। इस दौरान अध्यक्षीय चेयर पर पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल मौजूद थे।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव खारिज होने के बाद कार्यवाही

- विपक्ष के हंगामे में बीच ध्वनि मत से प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

गृहमंत्री अमित शाह के वक्तव्य के दौरान ही विपक्षी सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर हंगामा करने लगे। इसी बीच प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ और ध्वनि मत से प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया था, लेकिन कई सदस्यों ने अपने वक्तव्य में उनसे हटकर सरकार की आलोचना की है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के प्रस्ताव की निंदा की और कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इज़रायल के प्र.मंत्री बैंजमिन नेतन्याहू, ईरान के हवाई हमले मारे गए हैं?

ईरान सरकार से सम्बद्ध तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के अनुसार केवल इज़रायल के प्र.मंत्री ही नहीं, उनके भाई ईडो नेतन्याहू व राष्ट्रीय सिक्युरिटी मिनिस्टर इटमार बैन गवीर भी मारे गए हैं

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 11 मार्च। शानदार सिद्धांत या साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जैसी रणनीतियों के लिए युद्ध बेहद उपजाऊ माहौल देता है। हाल ही में सनसनीखेज अफवाहें सामने आई हैं, जिनमें कहा गया है कि इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी हवाई हमलों में मारे गए हैं।

हालांकि इजरायली अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों ने इन दावों को ''झूठी खबर'' बताया है, लेकिन ईरान से जुड़े सरकारी मीडिया, जिसमें तसनीम न्यूज़ एजेंसी भी शामिल है, ने कहा है कि न केवल नेतन्याहू मारे गए हैं, बल्कि उनके भाई इडो नेतन्याहू और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर भी मारे गए हैं। ये अफवाहें कल से सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- यह भी सच है कि गत तीन दिन से प्र.मंत्री नेतन्याहू की कोई विडियो या फोटो भी रिलीज नहीं की गई है, जबकि इस युद्ध के पहले अभुमन तीन-चार विडियो जारी किये जाते थे नेतन्याहू की दिन भर की गतिविधि के बारे में।
- इसके अलावा गत तीन दिन से नेतन्याहू के केवल लिखित वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं।
- साथ ही ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के अनुसार 8 मार्च से नेतन्याहू के निवास की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है और इन्हीं दिनों अमेरिका के दो प्रतिनिधी जैरेड कुश्नर व स्टीव विटकॉफ की पूर्व निश्चित यात्रा भी अचानक कैंसिल की गई है।
- नेतन्याहू व फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रां की टेलिफोन वार्ता का केवल लिखित मजमून जारी किया गया है, उसके साथ कोई ऑडियो या विडियो क्लिप संलग्न नहीं है तथा लिखित वक्तव्य में यह भी उल्लेखित नहीं है कि वार्ता कब और कहां हुई थी।

घरेलू एलपीजी की आपूर्ति फिलहाल तो स्थिर हो गई है

लेकिन अब सरकार को एक मजबूत टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था बनाने के लिए काम करना होगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मार्च। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच रसोई गैस यानी एलपीजी की घरेलू उपलब्धता को प्राथमिकता देने का सरकार का तेज कदम यह दिखाता है कि भारत में खाना पकाने के ईंधन के राजनीतिक और सामाजिक महत्व को वह अच्छी तरह समझती है। रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देना, रीफिल बुकिंग को नियंत्रित करना और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना, इन फैसलों से नीति निर्माताओं ने भू-राजनीतिक अनिश्चितता से हिल चुके बाजार को स्थिर करने की कोशिश की है। फिलहाल तत्काल लक्ष्य, यह सुनिश्चित करना कि करोड़ों भारतीय रसोइयों में गैस खत्म न हो, कुछ हद तक हासिल होता दिख रहा है।

लेकिन हाल की घटनाएँ यह भी बताती हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें नीति निर्माता नज़रअंदाज नहीं कर सकते।

पहला, कीमतों का संकेत पहले ही चेतावनी दे रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हाल में 200-250 रुपये की बढ़ोतरी और घरेलू एलपीजी दरों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी यह दिखाती है कि वैश्विक अस्थिरता कितनी तेजी से स्थानीय महंगाई में बदल सकती है। रसोई गैस घर के खर्च का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए। अगर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहता है, तो सरकार के सामने कठिन विकल्प होगा, या तो कीमतों को और बढ़ने दे या उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी बढ़ाए। दोनों ही विकल्पों का असर सरकारी वित्त पर पड़ेगा।

दूसरा, लिक्विफाइड नैचुरल गैस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ईरान वॉर के कारण रसोई गैस की भारी किल्लत हो गई है, हालांकि, सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में स्थिरता लाने के प्रयास किए हैं और किसी हद तक सरकार को इसमें सफलता भी मिलती दिख रही है।
- पर कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति पर भारी संकट है, दाम बढ़ने के बाद भी आपूर्ति नहीं हो रही है इससे कई छोटे प्रतिष्ठान तो बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं, खासकर वो जो कम मुनाफे पर काम करते हैं।

कांग्रेस प्रत्याशी की जीत बनी हार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मार्च। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के एक नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है और भाजपा नेता तथा पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को सही विजेता घोषित किया है।

यह फैसला रावत द्वारा दायर चुनाव याचिका पर आया है। उन्होंने आरोप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर हारे हुए भाजपा प्रत्याशी राम निवास रावत को विजेता घोषित किया।

क्या ट्रंप युद्ध खत्म करने के विकल्प ढूंढ रहे हैं?

चर्चा है कि अमेरिका और इज़रायल के हमलों का ईरान ने ऐसा करारा जवाब दिया है, जिसकी ट्रंप को उम्मीद नहीं थी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मार्च। ''ट्रम्प ऑलवेज़ चिकन्स आउट'' (टीएसीओ) अर्थात ट्रंप हमेशा डर जाते है, यह थ्योरी ईरान के साथ युद्ध के बारे में प्रमुख आख्यान बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ईरान के साथ अपने युद्ध प्रयासों को समाप्त करने के तरीके ढूंढने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जैसा कि उनके बयानों से प्रतीत होता है।

ट्रम्प के शक्ति प्रदर्शन पर ईरान के करारे जवाब ने अमेरिका को युद्ध खत्म करने के तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बार-बार कहा कि युद्ध जल्दी समाप्त होना चाहिए। ट्रम्प ने अपनी विशिष्ट शैली में ''विशाल लाभ'' का दावा किया।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्रम्प ने अमेरिकी युद्ध प्रयासों और जीवन और संसाधनों के संदर्भ में हुए नुकसान को बेहद मामूली कहा। जैसे, जीवन के नुकसान सिर्फ एक छोटी सी कीमत हो।

यह स्पष्ट था कि अमेरिकन चाहते हैं कि करारी हार से पहले ही युद्ध खत्म हो जाए। विश्व के बाजारों में तेल की कमी के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि, वैश्विक मंदी का खतरा, और स्टॉक बाजारों में गिरावट के चलते अमेरिकी प्रशासन पर गंभीर दबाव पड़ा है।

इसके विपरीत, अमेरिका और इज़रायल से मिसाइलों के हमलों और बमबारी के बावजूद, ईरान का कहना है कि युद्ध का कोई तत्काल अंत नहीं होगा और ईरान संघर्ष जारी रखेगा। अपने मिसाइल हमलों को धीमा करने के बजाय, ईरान ने अपनी अग्नि शक्ति बढ़ा दी है।

ईरान ने तीखी बयानबाजी की कि क्षेत्रीय देश, जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अमेरिका के साथ हैं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने मंगलवार को अपनी ''मास्टर मिसाइल्स'' की घोषणा की, जो और ज्यादा विध्वंसक हैं।

अमेरिकी युद्ध मशीन ने होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से तेल के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इसी बीच एक बार फिर चर्चित थ्योरी ''टाको'' (टीएसीओ) सुर्खियों में है, यानि ''ट्रंप ऑलवेज़ चिकन्स आउट,'' अर्थात् ट्रंप हमेशा डर जाते हैं।
- ट्रंप युद्ध खत्म करने के विकल्पों पर तो वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में पुतिन से भी वार्ता की है पर आदत के अनुसार वे शेखी बघारना नहीं भूलते, ईरान हमले में उन्होंने भारी लाभ का दावा किया, तथा अमेरिका को हुए जानमाल के नुकसान को बेहद मामूली करार दिया।
- असल में अमेरिका के लोग चाहते हैं कि और भारी नुकसान हो, इससे पहले ही युद्ध खत्म हो जाए क्योंकि तेल की कमी के कारण महंगाई बढ़ रही है, शेयर बाजार गिर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है, जिससे अमेरिकी जनता और प्रशासन भारी दबाव में हैं।

ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 से नाम वापस लिया

तेहरान, 11 मार्च। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच खेल जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसकी नेशनल फुटबॉल टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। ईरान के खेल मंत्री अहमद दोनजामाली ने टीवी पर इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में उनकी टीम के लिए अमेरिका में जाकर खेलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे।

- ईरान के खेल मंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात में उनकी टीम का अमेरिका जाकर खेलना संभव नहीं है।

खेल मंत्री ने अपने बयान में कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या के बाद देश की सरकार ने यह कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका -इज़रायल ईरान युद्ध अब ''ऑयल प्राइसिस'' पर नियंत्रण रखने के जंग में तब्दील हुआ?

ट्रंप अब सार्वजनिक रुप से वादा कर रहे हैं कि ऑयल व गैस की कीमत कम करा लेंगे, पर दूसरी ओर ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर एक बूंद ऑयल नहीं ले जाने देगा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मार्च। ईरान और अमेरिका-इज़रायल गठजोड़ के बीच चल रहा पश्चिम एशिया का युद्ध अब होर्मुज़ स्ट्रेट और तेल की कीमतों पर आकर केन्द्रित होता दिखाई दे रहा है। युद्ध के बारहवें दिन होर्मुज़ स्ट्रेट के पास पहुँच रहे और आसपास के पानी में चल रहे तीन जहाजों पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, इनमें एक थाई कार्गो जहाज भी शामिल है।

ईरान ने धमकी दी है कि वह होर्मुज़ स्ट्रेट से ''तेल की एक भी बूंद'' गुजरने नहीं देगा। दूसरी ओर डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के जहाज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देते हुए साथ चलेंगे।

स्ट्रेट को खुला रखने की अपनी कोशिश में डॉनल्ड ट्रंप ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों से यह अपील तक की कि वे हिम्मत दिखाएँ और स्ट्रेट के संकरे पानी से होकर गुजरें। तथापि, मस्र्क और हापाग लॉयड जैसी सभी बड़ी शिपिंग कंपनियाँ अब इस खतरनाक पानी से दूर ही रह रही हैं।

इसके साथ ही, ईरान ने अब अपनी रणनीति को इकोनॉमिक वॉर फेयर में भी बदल दिया है। उसने कहा है कि क्षेत्र के वित्तीय संस्थान और अमेरिका के सहयोगी देशों के वित्तीय संस्थान हमले के वैध लक्ष्य हैं। वित्तीय संस्थान सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे पश्चिम एशियाई देशों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके वैश्विक संबंध भी हैं।

इन नई चुनौतियों ने तेल की कीमतों, शेयर बाजारों और सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर बढ़ने की आशंका से पैदा हुई अस्थिरता को कम करने की डॉनल्ड ट्रंप की योजनाओं को बिगाड़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ईरान ने युद्ध की रणनीति का विस्तार करते हुए दावा किया कि अमेरिका व उसके मित्र देशों के वित्तीय संगठन को भी अब युद्ध का टारगेट बनाना पूर्णतया जायज है।
- जैसा कि स्पष्ट ही है, पश्चिमी एशिया के देश, जैसे सऊदी अरब, यू.ए.ई., कतर व बहरीन के काफी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सम्बंध है। अतः ईरान द्वारा इन देशों की वित्तीय संस्थाओं व संगठनों को आक्रमण का जायज ''टारगेट'' घोषित करना इन देशों के लिए खतरे की घण्टी है।
- युद्ध के कन्फ्यूज़न में अमेरिका ने भी अफवाहें व फर्जी खबरें फैलाना शुरु किया। एक खबर यह फैलाई कि अमेरिका के युद्ध पोतों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से एक जहाज को सुरक्षित पार करवाया। पर बाद में स्वयम् अमेरिका ने इस दावे का खण्डन किया।
- दूसरी ओर ईरान ने तीन जहाजों को मिसाइलों से क्षति पहुंचाई, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के पानी के नजदीक तैर रहे थे।
- दावों, घोषणाओं व खण्डनों से यह तो स्पष्ट हुआ कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर कब्जा बरकरार है।

भारत में गहराया खाद संकट

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 11 मार्च। पिछले 12 दिन से ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका-इज़रायल युद्ध के तरीकों तथा तेहरान के ड्रोन हमलों ने पारंपरिक इंटरसेप्ट समीकरणों को चुनौती दे रखी है। अमेरिका-इज़राइल युद्ध ने युद्ध के तरीके को फिर से परिभाषित किया है तथा तेहरान द्वारा ड्रोन-नेतृत्व वाले विषम हमले ने पारंपरिक इंटरसेप्ट समीकरणों को चुनौती दी है।

लेकिन उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव अब बेहद संकटप्रद होते जा रहे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ईरान युद्ध के कारण एलपीजी, पैट्रोल - डीज़ल संकट के बाद खाद संकट भी गहरा रहा है। इसका दूरगामी असर कृषि सैक्टर पर निर्भर रोजगारों पर पड़ेगा।